CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Steep rise in the inflation and its adverse impact on the Economy and the People—*contd:*

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): धन्यवाद महोदया, मैं डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है इसलिए मैं किसी भी बात की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। फिर भी मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जीवनावश्यक चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं और लोगों को उसके संबंध में आपत्ति हो रही है, उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। महोदया, बहुत सारी चीजें जो रोज के हमारे खान-पान में रहती थीं, ऐसी चीजें खान-पान की थाली से गायब हो रही हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है और इस पर गौर करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ दो बातें इस संबंध में रखना चाहता हूं। इस गवर्नमेंट के आने के पहले महाराष्ट्र में प्याज का भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था कि हद से बाहर जा रहा था। तब नेफेड के माध्यम से जो प्याज ऐक्सपोर्ट हो रहा था, उसके लिए हमने—क्योंकि प्रोडक्शन कम थी इसलिए भाव बढ़ रहे थे तो नेफेड के जरिए जो प्याज बाहर जा रहा था, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। उसके रुकते ही ब्याज का भाव स्थिर हो गया। नीचे आ गया। मैं आदरणीय मंत्री जी को सतर्क करना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमारे देश से बहुत सारी सब्जियां—प्याज, बटाटा आदि ऐक्सपोर्ट हो रही हैं। जब प्रोडक्शन कम हुई है तो चन्द दिनों के लिए, प्रोडक्शन लैवल पर आने तक क्या हम इस संबंध में कुछ सोच सकते हैं कि बाहर ऐक्सपोर्ट बंद कर दें ताकि लोगों के खाने-पीने के लिए यह चीजें उपलब्ध हो सकें। मेरा अनुरोध है कि आप इस संबंध में जरूर विचार कीजिए। दूसरी बात मैं यह सजैस्ट करना चाहता हूं कि गांव से जब सब्जियां शहरों तक आती हैं तो यह सब सब्जियां डायरैक्ट बाजार में आ जाती हैं। तो ट्रेडिंग के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू करके उनको यदि हम प्रोत्साहित करने की कोशिश करें कि वहां ही इन सब्जियों की कटाई करके, उसकी ड्रैसिंग करके, उन्हें ठीक ढंग से पैक करके—खास करके यह महानगर जो है यहां पर लोगों को सिखाकर इस तरह से सब्जियां लाने का इंतजाम किया जाए। यह परमानैंट इस्टैब्लिशमेंट होगी। इसकी वजह से वहां के लोगों को उद्योग मिलेंगे, वहां के लोग जो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, इस पर रोक लगेगी और लोगों को ड्रैसिंग की हुई तरकारी, भाजी बाजार में मिल सकेगी। इस विषय पर अगर आप विचार कर सकते हैं तो अवश्य करिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने यहां पर सब सदस्यों का भाषण सुनते समय देखा कि सबने सिर्फ ट्रेडर्स को ध्यान में रखकर उनके ऊपर हमला किया है। ट्रेडर्स किसके साथ हैं? वह हमारे साथ हैं या तुम्हारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा हुई। मैं साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि किसी को भी स्टेट-वे करके, किसी भी कम्युनिटी को स्टेटवे करके चाहे वह ट्रेडर्स हों या और कोई हो उसके ऊपर टारगेट करके हमला मत कीजिए। इस प्रश्न का हल ढूंढना है, इस प्रश्न को मिटाना है तो उसकी जड़ तक जाना चाहिए और इसके संबंध में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, नहीं तो बाकी सब चीजों के दाम भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इसी चीज के दाम बढ़े, बाकी सब चीजों के दाम भी बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, राशन के दाम बढ़े या इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़े जब इनके दाम बढ़ते हैं तो हम सब लोग तुरन्त उसके ऊपर एक-दो दिन के लिए हमला कर देते हैं और बाद में चुप बैठ जाते हैं। जब सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो हम सब चीजों के बढ़े हुए दाम देने लगते हैं। इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन आ गया, मोबाइल टेलीफोन भी आ गया हम उसके भी बढ़े हुए दाम दे रहे हैं। तो इस विषय पर सिर्फ स्टेटवे करके यह कहना...यह ठीक नहीं रहेगा। यह मेरे कहने का मतलब है। मैं मंत्री जी से एक और प्रार्थना करूंगा। मैंने महाराष्ट्र में देखा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको हम ट्रेडर्स को सौंप देते हैं। ट्रेडर्स गांव में जाकर अपना माल बेचते हैं। हमारा जो कंट्रोल्ड प्राइस का सामान है वह उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, वे सब चीजों को इधर-उधर कर देते हैं। अगर इसके ऊपर कंट्रोल लाना है तो जो ट्रेडर्स हैं, जो पीडीएस के अन्दर सर्विस देने वाले हैं उनको कोई भी दूसरा माल बेचने पर पाबन्दी लगनी चाहिए। इतना करोगे तो यह सब बन्द हो जाएगा। इतना ही मेरा कहना था। धन्यवाद!

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, a lot of people, people from all the political parties, have spoken. Let the Minister reply now because there is nothing to add to what has been said. (*Interruptions*). Mr. Dasgupta, if I allow you, then I have to allow three people, two others from there.

SHRI MD. SALIM: Madam, Let the Minister reply. Then if we have any questions, we can put them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Questions, you can put. But basically, a full debate has taken place. If you put relevant questions, the Minister will reply. But, you cannot add anything to the price rise and a lot has been spoken.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर जो प्राइस राइज का है बहुत चर्चा हुई, निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपके सामने जो विषय रखना चाहता हूं, जो इससे संबद्ध विषय है वह यह है कि इन्फ्लेशन का देश की आर्थिक नीति पर, देश के आर्थिक ढांचे पर क्या असर पड़ा है। यह विषय बिल्कुल छूट गया है। अगर यह विषय छूट गया है तो ....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you one thing, Mr. Agarwal, if you can have your seat. The basic idea was to discuss the effect of the price rise and not the entire economic system in the country. We had a discussion on the Finance Bill, we had a discussion on the Appropriation Bill which the Finance Minister brought. You could have taken that issue now. But just now, the focus is on price rise. That is why, if you look at his statement also, it only deals with onions, potatoes and other essential commodities. If you are planning to discuss the entire economic situation and the decline in the economy, I think we should have a full-fedged discussion. I will be with you on it. But just now, we cannot open a new topic. I agree that the topic is deceiving. But the basic underlying thing in it is, Members are very concerned about the price rise and they thought that it was not taking place just at random, there was some reason in the economic system which was causing it. That is why the Finance Minister was asked to come here. Otherwise, it would be Mr. Barnala who would come to answer. That is the basic reason.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, my question is very specific.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your question?

DR. BIPLAB DASGUPTA: My point is, in this statment, the Finance Minister has tried to explain what went wrong with the earlier Governments and has said that production has gone down and so on and so forth. His stand has been that he is not responsible for this inflation which has taken place. What has the Government done to control the iflation after coming to power? When the Government came to power, it was at five per cent. Earlier, at some stage last year, it was three per cent. Now, it has gone up to 8 per cent. Within three months, it has gone from five per cent to eight per cent. It is a very substantial increase. The Government has to explain that thing and not what has happened before. It is related to that. I agree that the earlier Governments also did not perform well in so far as agriculture is concerned. It is true that despite eleven successive good harvests, our agriculture has done very badly over the last few years. I don't know why that is so. But that is one of the major reasons. The question is, if this is what has landed us in this situation, what policy change has the new Government taken which would help us to really combat the situation and to increase the agricultural production? In this Budget, I don't find any radical change either on the question of subsidy or on the question of capital investment on agriculture. There has been no radical change from the policies which had been followed earlier. Related to that, there is another question about the diversion of resources.

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Biplab Dasgupta, I explained the same thing to Mr. Agarwal. Unfortunately, you were not here when we had the discussion on the Finance Bill.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, I was here and I had spoken on the Finance Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, you were here and you had spoken on the Finance Bill. Then you should have spo-

ken about this thing at that point of time. Just now, the focus should not be diverted. The focus of the nation today is on the increase in prices, and that is why I repeat it that it was not only the Opposition but the ruling party Members had also shown their concern over this issue. So, there should be no two opinions on this subject. Let the Finance Minister say what he has to say.

श्री ओंकार सिंह लखावत: महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मूल्य वृद्धि चल रही है इसके लिए मंत्री जी आने वाले एक महीने तक क्या प्रभावी कदम उठाने वाले हैं और आने वाले चार-छः महीने में इसका क्या असर पड़ेगा समय रहते अपने उत्पादन और मांग को ध्यान में रखते हुए और आने वाले सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ताकि हम जो आज यहां चर्चा कर रहे हैं, शीतकालीन अधिवेशन में यह चर्चा न करनी पड़े। इस बारे में मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं।

SHRI JIBON ROY: Madam, I want to know from the Minister as to what steps he is taking to widen the PDS base. Secondly, the lowest paid workers are very severely affected due to the price rise. What steps is the Government taking to link up the price increase with the minimum wage level?

श्री रामदास अग्रवाल: यहां जो क्वेश्चन हो रहे हैं, उनका मंत्री जी जवाब देते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agarwal Ji, this is enough.

श्री रामदास अग्रवाल: मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96 में अप्रैल से लेकर सितम्बर तक हमारा इन्फ्लेशन रेट 9 परसेंट से लगभग 11 परसेंट तक रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आठ परसेंट हुआ है तो क्या प्याज और आलू की वजह से हो गया? जब 1995-96 में इन्फ्लेशन रेट 11 परसेंट था तो क्या आलू और प्याज के भाव इससे भी ज्यादा थे? या केवल इन दो वस्तुओं के कारण सारे इन्फ्लेशन रेट दो या तीन परसेंट बढ़ गए हैं? मैं कोई स्टेटिस्ट या अर्थशास्त्री नहीं हूं मैं अर्थ जरूर डील करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कि क्या इन दो कमोडिटीज के कारण इतना ज्यादा असर पड़ गया है? जब 1996-97 में इन्फ्लेशन रेट 4.6 परसेंट था, जबकि हमारे दूसरे लोग राज कर रहे थे उस समय क्या इकनोमी बढ़ गई थी, और उसके कारण मंदीवाद नहीं आया था?

उपसभापति: अग्रवाल जी, जो उन्होंने पूछ लिया है उस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं।

Mr. Agarwal, you are referring to paragraph 3 of the Minister's statement in which he has very clearly stated all these things. That is all. You are just elaborating it. So, he will answer it. *(Interruptions)* I do not know whether you are supporting him or opposing him.

श्री रामदास अग्रवाल: महोदया, मैं अपोज नहीं कर रहा हूं। मैं अपने उत्तरदायित्व को समझता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 11 परसेंट इन्फ्लेशन हो रहा था उस समय भी हमारे दाम इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे? हमको चिन्ता जरूर हुई होगी? उस वक्त में भी यहां सदन में था। उस वक्त हम भी यहां सदन में समय-समय पर इस बारे में चिंता व्यक्त करते रहे हैं, भावों की, अभावों की। लेकिन सवाल यह आता है कि जब 11 प्रतिशत था, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट के बावजूद भी इन चीजों के दाम नहीं बढ़े। तो कौन सी चीजों के दाम बढ़ गए जिसके कारण यह असर आया? आज केवल आलू प्याज के दाम बढ़े हैं, ऐसा सब ने माना है। तो क्या केवल इसके कारण दो प्रतिशत, ढाई प्रतिशत इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, यह तथ्य हमारी समक्ष में नहीं आ रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वे आज या किसी और अवसर पर, जब वे चाहें इस बात को हमें बतायें जिससे हमारा ज्ञानवर्धन हो सके कि क्या केवल दो वस्तुओं के कारण इस देश में इन्फ्लेशन रेट दो या तीन प्रतिशत बढ़ गया? यह तथ्य हमारे सामने आना चाहिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more questions. Please sit down. My patience is now bursting at the seams, and so is the Minister's. I am sorry, मिनिस्टर जो बोलिए, किसी ने कोई नई बात नहीं बोली। I have heard the entire debate and I can sum it up in five lines that the prices have gone up. Some said, "It is due to the bomb blasts." Some said, "It is due to mismanagement." Some said, "It is due to them." The other side said, "No; it was due to them also." I know what it is. The Minister will reply. ...(*interruptions*)... Let him reply. He brought the Budget.

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभापति महोदया, मैं अत्यन्त ही आभारी हूं इस सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सरकार का ध्यान इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आज आकर्षित किया है। मैं उन सारे सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस अत्यन्त ही जीवन्त चर्चा में भाग लिया है और अपने-अपने दृष्टिकोण से इस पूरे विषय को सदन और देश के सामने रखने का प्रयास किया है।

महोदया, आपने निर्देश दिया है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए, इसकी सामयिक अनुकूलता को देखते हुए हम इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श करें और जो सार्थक प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों पर यहां पर चर्चा हो। आपने यह भी कहा है और जिसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि चूंकि मुद्रा-स्फीति या बढ़ती कीमतें अकेले किसी राजनैतिक दल का विषय नहीं है, इसलिए हम सब को यहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए। आपके आने से पहले महोदया, यह चर्चा प्रारम्भ हुई थी और कई सदस्य आपके आने से पहले चर्चा में भाग ले चुके थे, अपने-अपने विचार रख चुके थे और चर्चा ने एक ढर्रा पकड़ लिया था। उस ढर्रे में बहुत सारी राजनैतिक बातें आ गई थीं। लेकिन बिना किसी राजनैतिक विवाद में पड़े मैं कुछ तथ्यों की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सरकार के बारे में जो बातें कही गई हैं उनके बारे में सरकार का पक्ष रखना चाहूंगा।

महोदया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र जॉर्ज फर्नांडिस अपने दल के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में यहां पर उपस्थित हैं। आज के दिन उन्होंने इस चर्चा में भाग भी लिया है। इससे पहले, इस सदन का परित्याग करने से पहले माननीय नेता विरोधी दल ने भी जो वक्तव्य यहां रखा उसमें उन्होंने इस विषय की भी चर्चा की है और इससे संबंधित जो आर्थिक पहलू हैं, उस पर भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण से रोशनी डालने का प्रयास किया है।

महोदया, एक असत्य जो बहुत दिनों से इस देश में चल रहा है, जिसका उल्लेख एक बार फिर श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इस सदन में किया है, वह यह है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 1991 में थी तो उस समय मुद्रा-स्फीति 16-17 परसेंट, पता नहीं कितनी थी। मैं जब इस सदन का सदस्य था, इसके पहले इस विषय पर चर्चा होती थी तो मैंने इसके बारे में जो सच्चाई है वह सदन में बार-बार रखने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी इस प्रकार की भ्रम की स्थिति और इस प्रकार की गलत धारणा यदि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सदस्य के मन में है तो मैं समझता हूं कि इसका खुलासा करना, स्पष्टीकरण करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आज की परिस्थिति में और उस समय की परिस्थिति में कुछ लेना-देना है। मैं इसके संबंध में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। 22 या 21 जून, 1991 को कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। उस सप्ताह जो मुद्रस्फीति की दर थी वह 12.1 प्रतिशत थी। यह सरकार के आंकड़े हैं, वही आंकड़े हैं जिस पर हर सरकार निर्भर करती है, भरोसा करती है, सदन के सामने और संसद् के सामने रखती है। 12.1 प्रतिशत 22.6.91 को थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो मुद्रस्फीति का क्या हुआ? यह बढ़ते-बढ़ते 24 अगस्त, 1991 को, फर्नांडिस जी नोट करें, यह बढ़ कर 16.7 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। इसलिए... **(व्यवधान)**

SHRI JOHN F. FERNANDES: The legacy which we got from the previous Government was a destroyed economy

SHRI YASHWANT SINHA: I am very glad that you have walked into the trap that I laid.

SHRI JOHN F. FERNANDES: I have said it, Madam, because the economy has been destroyed in those two years.

श्री यशवंत सिन्हा: बिलकुल आपने सही कहा।

उपसभापति: वह अकेले हैं। उनके मददगार नहीं हैं तो आप उनके लिए ट्रैप लगा रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: मैंने कहा कि 24 अगस्त, 1991 को यह 16.7 प्रतिशत हो गयी और उसके बाद यह ऊपर ही ऊपर रही बहुत सप्ताह तक फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हुई। कब? जुलाई और अगस्त के महीने में। उस समय 1991 में यह स्थिति थी। अब क्या था, आपने कहा कि विरासत में मिली, मैं मानता हूं कि विरासत में मिली 1991-92 में यहां पर चर्चा हुई कि मनी सप्लाई कितनी बढ़ी है। जानकार लोगों ने, गुरुदास दासगुप्ता जी ने जब इस प्रश्न को उठाया, इसका सीधा संबंध मुद्रस्फीति से है, बिलकुल सही है, बिलकुल ही सही है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है, मैं यह कह रहा हूं यशवंत सिन्हा की बात छोड़ दीजिये, 1000 सर्वोत्तम वित्त मंत्री यदि किसी देश में साथ-साथ काम करना शुरू करते हैं, फिर भी यदि सरकार का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण के बाहर चला जाता है और यदि मुद्रा आपूर्ति जिसको हम इकोनोमिक्स में अर्थ-शास्त्र में एम-3 के नाम से जानते हैं, वह मुद्रा आपूर्ति यदि नियंत्रण के बाहर चली जाती है तो कोई

व्यवस्था ऐसी नहीं है जो तत्काल उसके ऊपर काबू पा सकती है जब तक कि उन सारे आंकड़ों को फिर से हम ऐसा मोड़ न दें कि वह पीछे की ओर जाने के लिए बाध्य हों। यह स्थिति है। 19 प्रतिशत से उस समय मुद्रा आपूर्ति एम-3 सप्लाई बढ़ी थी 1990-91 में, 1991-92 में 19.3 प्रतिशत हुई, उसके बाद आपने कंट्रोल किया। लेकिन कांग्रेस की रिजीम में ही यह फिर भागा और मैंने यहां पर इसके बारे में कुछ सोचा ऐसा नहीं, मैं जान रहा था कि यहां पर चर्चा होगी, मुद्रस्फीति, बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा होगी, सरकार बचाव की मुद्रा में रहेगी क्योंकि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए यहां पर खड़े हो कर मैं सदन के सामने इस बात को कतई नहीं कह सकता हूं कि कीमतें नहीं बढ़ी है। इसलिए इसके कारणों में जाने का काम मैंने किया। पिछले साल 1997-98 में, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों को रख रहा हूं, सारा सदन जानता है क्योंकि बार-बार इसकी चर्चा इसी सदन में हो चुकी है। जैसे आपने कहा, हमने बजट पर चर्चा की, एप्रोप्रियेशन बिल पर चर्चा की और यहां वित्त विधेयक के ऊपर चर्चा की।

हमने चर्चा की इस बात की कि क्या हुआ पिछले साल 1997-98 में। यह हुआ कि, उन्होंने कहा बजट के अनुमानों में कि हम राजकोषीय घाटे को, फिसकल डिफिसिट को 4.5 प्रतिशत पर सीमित रखेंगे। जो आंकड़े आज तक आए हैं उनके अनुसार यह राजकोषीय घाटा बढ़ गया 6.1 प्रतिशत। सकल घरेलू उत्पाद का हो गया। इसमें 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि साल भर में हुई। सरकारी घाटे में 20 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। तो मैं वापस गया इतिहास में। मैंने कहा कि इस तरह का घाटा जिसमें कि जो फिसकल डिफिसिट के टारगेट्स थे वे इतने भयंकर ढंग से कब ध्वस्त हुए तो मैंने देखा कि 1993-94 में राजकोषीय घाटा जिसको उस समय के वित्त मंत्री, आज के विरोधी दल के नेता—जो दुर्भाग्य से सदन में उपस्थित नहीं है—ने कहा था बजट के अनुमान में कि हम राजकोषीय घाटे को 4.6 प्रतिशत पर नियंत्रित करके रखेंगे 1993-94 के बजट में। अंततः राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 7 प्रतिशत को लांघ गया था। शायद 7.4 प्रतिशत उस साल का राजकोषीय घाटा हुआ। तो उस समय का जब राजकोषीय घाटा यह हुआ तो मैंने उस समय के आंकड़े लिए और मैंने देखा कि राजकोषीय घाटे में 20 हजार करोड़ रुपए की अगर एक साल में — 23 हजार करोड़ उस साल रहा—जब इतनी वृद्धि हो जाती है तो 40 हजार से हम 60 हजार के ऊपर चले गए। पिछले साल हम 66 हजार पर थे और 86 हजार के ऊपर चले गए। जब-जब देश में इतनी बड़ी राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है तो उसका नतीजा क्या हुआ है ...**(व्यवधान)**

SHRI JIBON ROY: What will happen to the people? He is talking about the previous Governments. What steps is he taking? *(Interruptions)*.

श्री नीलोत्पल बसु: क्या फायदा हुआ मैडम जो आपने डायरेक्शन दिया था ...**(व्यवधान)**

उपसभापति: जवाब पूरा नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)** Let him complete.

SHRI JIBON ROY: He is blaming the previous Government. *(Interruptions)*.

SHRI JOHN F. FERNANDES: We are concerned about the present situation. He cannot justify it because it has happened. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. He has not completed his speech. *(Interruptions)*.

SHRI JIBON ROY: Madam, the Minister in his statement has said that the Government has nothing to do with it ...*(Interruptions)*... We want to know what steps he is going to take. We would like to know what measures they have taken. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, the Minister is *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. ...*(Interruptions)*.

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, I am not yielding. I have listened to the speeches *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Jibon Roy, please sit down.

SHRI YASHWANT SINHA: I have listened to all the speeches in all humility. I have taken the criticism which has been levelled against the Government in all humility. Shri Gurudas Das Gupta has gone to the extent of saying that by suppressing facts, I have committed a fraud on the people and on this House. I am trying to put some facts before the House. *(Interruptions)*.

— 3529/RS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak.

SHRI YASHWANT SINHA: I want that all the facts must come before the House. *(Interruptions)*.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Shri Biplab Dasgupta, I am not allowing you. Please sit down.

SHRI YASHWANT SINHA: I will reply to all the points which you have made because I consider this to be a very important issue. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. When you were speaking, you levelled certain charges which you though were correct. The Minister listened to those charges. It is his prerogative to reply to the points the way he feels he can build his reply. You cannot direct the Minister to reply in the way in which you want. The Minister cannot direct you to put your question the way in which he wants. You should have some patience. Listen to him. I have allowed him to speak. Let him speak. If he is giving some theory which he feels is the cause of rise in prices, let him give. Whether you agree or not, that is a different matter. You can raise your objections later. Let him finish his speech. Have some patience. If you are hungry, go and have some food. But those who want to listen to him, let them listen to him.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, how can he explain in that way? *(Interruptions)*. How can he interpret.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him interpret in the way in which he likes. *(Interruptions)*. Mr. Biplab, you are a great economist. Please sit down. *(Interruptions)*. Mr. Jibon Roy, I don't want to name you. Please sit down.

SHRI YASHWANT SINHA: I am not done...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: If anybody interrupts the Minister, I will really name him because this is not the way you show your concern to the people. Let him finish his speech...*(Interruptions)* No, not now. Let him first finish his speech...*(Interruptions)*. Never mind. The damage won't be done. Already people are hungry. No more damage can be done. Let him first speak.

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, मैं सिर्फ एक साधारण सा सिद्धांत रख रहा था, एक साधारण सा तथ्य रख रहा था सदन के सामने कि जब-जब राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ...(व्यवधान)

उपसभापति: आप इतनी मुश्किल हिन्दी बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रही थी। ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा: नहीं समझ रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव: पहली बार तो हिन्दी में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपसभापति: इसलिए झगड़ा हो रहा है। ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: लेकिन रामगोपाल यादव जिस दल के हैं उस दल के नेता ने मुझे एक दिन रोक कर कहा कि आप सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, आपको हिन्दी में बोलना चाहिए। मैंने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और इसलिए मैं हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: इसलिए तो हम लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: तो महोदया, मैं यह कह रहा था कि 1993-94 और 1997-98 तथा उसका जो प्रभाव पड़ा अर्थात् 1994-95 के आंकड़ों पर और 1998-99 के आंकड़ों पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं, इन सारी कमोडिटीज़ की जो मुद्रास्फीति हुई वह 1994-95 में 4.7 प्रतिशत और 1998-99 में 4 प्रतिशत प्राइमरी आर्टिकल्ज़ में 8 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत, फूड आर्टिकल्ज़ में 11.7 प्रतिशत हुई और इस साल यह 11.6 प्रतिशत, सीज़नल आइटम्ज़ में 8.9 प्रतिशत तथा 8.8 प्रतिशत और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्ज़ जिसको अलग से छांट कर मैंने रखी है दोनों वर्षों की तुलना कर रहा हूं और ईमानदारी के साथ कर रहा हूं उस वर्ष 27.2 प्रतिशत तथा इस बार 41.4 प्रतिशत ...(व्यवधान) तो मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी,

मनी सप्लायी बढ़ेगी, तो उपसभापति महोदया, कीमतों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। दो प्रकार के फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला जो फैक्टर है वह यह है कि 1997-98 का वर्ष अत्यन्त ही बहुत बढ़े राजकोषीय घाटे का वर्ष रहा और उसका प्रभाव इस साल की कीमतों पर पड़ रहा है। दूसरा जो मैंने पक्ष रखा था वह रखा था जो मौसमी कारण हैं, जो सीज़नल फैक्टर्स हैं। अब मैं अगर कहूं कि इस समय जो जाड़े का मौसम था, वह थोड़ा लंबा खिंच गया, उस समय जाड़े के मौसम का अंत जब हो रहा था तो अप्रत्याशित, असामयिक बारिश हो गई, तो मुझे लगता है कि इसमें सदन में कोई मेरे से असहमत नहीं होगा, क्योंकि ये तथ्य हैं। यदि मैं कहूं कि उसके बाद उसका असर रबी की फसल पर पड़ा, रबी की फसल जो हमारे बाजारों में मार्च के महीने में आती है उसके ऊपर उसका असर पड़ा। उसके बाद फिर हम सब इस बात को जानते हैं कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी पड़ी इस देश में, इस सदन में यह सवाल उठा कि ढाई हजार से ऊपर लोग मौत के शिकार हो गए इस भयंकर गर्मी से, इस सदी का एक सब से भीषण गर्मी का मौसम इस साल रहा। हम सब जानते हैं और जो थोड़ा बहुत भी किसानों से या कृषि से संबंध रखते हैं, वे जानते हैं कि एक प्री खरीफ फसल होती है, खरीफ के पहले, जिसको कहीं-कहीं अगहनी भी कहते हैं, बिहार में उसको अगहनी कहते हैं, तो उसमें जो बोने का काम हुआ, वह बीज जो था वह खेतों में सूख गया इस भयंकर गर्मी में वह प्री फसल जो होती है वह मार्केट में अभी जुलाई-अगस्त में आती है। उसके आने से कीमतों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण होता है। अब की क्या हुआ कि रबी की फसल भी मारी गई, और अगहनी की फसल, प्री खरीफ फसल भी मारी गई और इन दोनों फसलों की बर्बादी या कम पैदावार होना ही कारण हैं। जो आंकड़े मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में दिए हैं कि कितने की पैदावार में गिरावट हुई, 60 लाख टन आलू इस साल कम हुआ है, 6 लाख टन प्याज़ इस साल कम हुआ है, 13 लाख टन आयल, सीड्ज़ इस बार कम हुए हैं और ये सारे आंकड़े मैं सदन के सामने रख चुका हूं। तो यह एक दूसरा फैक्टर था जिसका असर कीमतों पर पड़ा है। ...(व्यवधान) मैं भाग नहीं रहा हूं मैं एक मिनट के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन कारणों को समझें और मैंने अगर इस तरह से इन कारणों का विश्लेषण किया है...।

और यदि मैं गलत हूं तो मैं चाहूंगा कि सदन मुझे करेक्ट करे, मुझे सही करे ताकि मैं सही दिशा में जा सकूं जिस से कि हम देश की समस्या का समाधान ढूंढ सकें।

मैडम, इस में राजकोषीय घाटे के बारे में मैंने कहा है कि हम इस को 5.6 प्रतिशत इस साल रखेंगे। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने उस को बहुत घटा दिया है, लेकिन मैं इस बारे में यथार्थ से अलग कर के कोई आंकड़ा सदन के सामने बजट के समय नहीं रखना चाहता था और इसीलिए मैंने 5-6 प्रतिशत की बात की है। अब क्या हम उस को मेंटेन कर पाएंगे? यह सवाल बजट की डिबेट में भी उठा था और यह सवाल आज के दिन भी उठा है। कहा जा रहा है कि आप का राजस्व कम हुआ है, प्रथम तिमाही में राजस्व कम हुआ है। मैडम, मैं बताऊं कि यहां क्या हुआ था? यथार्थ यही है, जो मुझे सरकार में आने के बाद पता चला कि अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने पिछले वर्ष के 4-5 महीनों के अंदर उनकी मॉडवेट क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉ-बैक लोगों को लेने नहीं दी। उन्होंने कहा, नहीं तुम को कैश में देना पड़ेगा क्योंकि हम को राजस्व बढ़ाना है। मैडम, उस समय भी इस की चर्चा हुई थी और आज फिर उस की चर्चा हो रही है। प्रथम तिमाही में राजस्व की जो वृद्धि होनी थी, वह राजस्व वृद्धि नहीं हुई है, मैं सदन के सामने आज मानता हूं लेकिन में आज भी उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि आने वाले दिनों में जो कदम हम ने उठाए हैं, उन से राजस्व में वृद्धि होगी क्योंकि उस का जो इम्पैक्ट पिछली सरकार के कामों का पड़ना था, वह असर पड़ चुका है और अगली तिमाही में, अगले क्वार्टर में उस का असर घटेगा।

मैडम, दूसरे पिछली बार इसी पीरियड में मुद्रा आपूर्ति में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस बार वह 3.6 प्रतिशत है यानी कि हम ने उस को आधा परसेंटेज पॉइंट से इस साल कम रखा है और मैं सदन को पूरी गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ दो आश्वासन आज के दिन देना चाहता हूं। एक तो यह है कि हम मुद्रा आपूर्ति के ऊपर, एम-3 ग्रोथ के ऊपर इस साल पूरा नियंत्रण रखेंगे। मैं ने आर०बी०आई० के साथ चर्चा कर कहा है कि मुद्रा आपूर्ति की दर को इस साल के टार्गेट 15 से 15.5 प्रतिशत के भीतर रखना पड़ेगा ताकि इस का असर मुद्रास्फीति के ऊपर न पड़े। दूसरे मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस साल खर्चे को बजट प्रावधान के भीतर रखूंगा, किसी भी हालत में सरकारी खर्च को बढ़ने नहीं दूंगा और इस प्रकार राजकोषीय घाटे के ऊपर हम नियंत्रण रखेंगे और

राजकोषीय घाटे के ऊपर नियंत्रण रहेगा, मुद्रा-आपूर्ति के ऊपर नियंत्रण रहेगा तो कीमतों के ऊपर या इनफ्लेशन के ऊपर जो एक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर हम नियंत्रण रखने में सफल होंगे। मैडम, यहां पर सवाल उठाया गया कि आप करने क्या जा रहे हैं? यह सवाल बार-बार उठाया गया। मैडम, आर्थिक कारणों के बारे में मैं ने बताया कि क्या करने जा रहा हूं? मैडम, जो तात्कालिक कारण हैं, सामयिक हैं या जो मौसमी कारण हैं, उन के बारे में मैं ने अपने वक्तव्य में पहले से ही लिखा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर यहां पर एक बात उठाई गई कि मैं ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीं। यह कहा गया कि बजट के चलते मुद्रास्फीति बढ़ी है। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि हम को राजनीति से अलग हटकर इस बारे में चर्चा करनी है। हां, पैट्रोल की कीमत एक रुपया बढ़ी और वह किस कारण बढ़ी वह मैंने बताया है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पेट्रोल से ट्रक नहीं चलते, पैट्रोल से ट्रेन नहीं चलती, ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल से कोई गाड़ी नहीं चलती, वे सारी गाड़ियां डीजल से चलती हैं और इसीलिए हम ने जानबूझकर डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई। मैडम, जब रेलवे बजट बन रहा था तो रेलवे बजट में फ्रेट किसी चीज के ऊपर नहीं बढ़ाया गया। दोनों बजटों को मिलाकर ऐसी कोई बात नहीं है जिस से यह कहा जाता कि इस से मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। मैडम, मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी पांच साल के शासन में थी, उन्होंने तीन बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। जब यू०एफ० गवर्नमेंट पावर में थी तो उस ने दो बार कीमतें बढ़ाई और मेरे मित्र वेंकैया नायडू चर्चा कर रहे थे कि एक बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ाई थीं। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि यदि हम एक रुपए से कीमत बढ़ाते हैं तो वह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है और दूसरी सरकारें इन चीजों की अगर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा देती है तो उन का कोई असर नहीं होता है यह कौनसा नियम है जिस के तहत यह चलता है? भाग्य की बात में तो आप विश्वास नहीं करते। थोड़ा भगवान में विश्वास करो और भाग्य में करो, तब तो कल्याण ही हो जाए।

मैडम, मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूं कि यदि मैं कुछ करूं तो वह जो है बिल्कुल ही दोषपूर्ण हो जाता है और वही काम अगर पिछली सरकारें करके गई तो वह बिल्कुल गुणात्मक, गुण से भरा हुआ, सर्वगुण संपन्न माना जाता है। यह तर्क तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं पूरी, जितनी जोर से इस बात को कह सकता हूं उतनी जोर से, इस बात को कहना चाहूंगा कि बजट की वजह से कोई कीमतों में वृद्धि नहीं है। बजट में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस माननीय सदस्य कह रहे थे, गुरुदास दासगुप्त जी ने इस बात को बार-बार कहा, अन्य सदस्यों ने भी कहा, तो यह एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगी है? यह मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर लगी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, मैनुफैक्चर गुड का जहां तक सवाल है, इस साल इतने दिनों में उसमें जो वृद्धि हुई है कीमतों में, इनफ्लेशन में, वह 4.5 प्रतिशत मात्र ही है और यह 4.5 प्रतिशत है 11 जुलाई तक, जिसमें कि 41 दिन हमारे पोस्ट बजट के भी शामिल है। तो क्यों नहीं असर पड़ा? अब यह दोनों तर्क साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि बजट की जो मार है महंगाई के ऊपर, वह पूरी तरह से अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, आने वाले दिनों में होगी और अभी हमारे ईश दत्त यादव जी कह रहे थे कि उन्होंने पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, कि एक जून को क्या था और आज कितना बढ़ गया है। तो इसलिए सहज ढंग से बिल्कुल आसानी के साथ जोड़ देना कि यह बजट के चलते ही हुआ है, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। आप उसके विस्तार में जाएं, हम उन सारे प्रस्तावों का विवेचन करें, उनका विश्लेषण करें और उसके बाद मेरे ऊपर आरोप लगाएं कि आपके बजट के चलते मुद्रास्फीति बढ़ी है तो मैं स्वीकार कर लूंगा। मैंने तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया है एडीबल ऑयल के ऊपर और उसके चलते क्या कीमतें बढ़ गई? नहीं, नहीं बढ़ीं। हमारे पास उसके बाद के आंकड़े हैं, 10 जुलाई को हमने इम्पोर्ट ड्यूटी में 10 प्रतिशत की कमी की और उसके बाद देश भर से जो आंकड़े आए हैं, चाहे वह सरसों का तेल हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे ग्राउंडनट आयल हो, मुंगफली का तेल हो, सबकी कीमतों में गिरावट के आंकड़े हैं। जब इन आंकड़ों का सवाल उठता है तो, जैसा गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा कि यह फरेबी हैं, यह आंकड़े विश्वसनीय नहीं है, हो सकता है कि न हों।....**(व्यवधान)**....

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह तो हम दुकान का नाम जानना चाहते थे। ....**(व्यवधान)**....

श्री यशवंत सिन्हा: वह दुकानें भारत सरकार की हैं, जहां से यह आंकड़ें प्रचलित होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार रही हो, वह इन्हीं आंकड़ों को मानकर चली है, दूसरा कहीं ओर से नहीं लिए और यही हम लोग मानकर चले। आप मेरे साथ चलिए पहाड़गंज, फिर आप चलिए सरोजनी नगर, फिर आप चलिए लाजपत नगर, फिर आप चलिए आजादपुर,

फिर आप चलिए चैन्नई, फिर आप चलिए मुम्बई और हर जगह हम वहां चलकर आंकड़ें लाएंगे ....**(व्यवधान)**....

श्री मोहम्मद सलीम: आप कलकत्ता भूल गए।

†[श्री मोहम्मद सलीम : आप कलकत्ता भूल गए।]

श्री यशवंत सिन्हा: मैं कलकत्ता नहीं बोल रहा हूं, जानबूझकर कलकत्ता नहीं बोल रहा हूं। तो मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कीमतें जो हैं वह एक ही शहर में अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की होती है, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है और शायद देश भर में काफी कुछ अंतर होगा। लेकिन, कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, यह चिंता का विषय मेरे लिए भी है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह मेरे लिए है क्योंकि आज यह मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, मैं देश का वित्तमंत्री हूं। इसीलिए सबसे अधिक इस बात की चिंता मुझे करनी है। मैं किसी आंकड़ें को छुपाना नहीं चाहता। सी०पी०आई०, कंज्युमर प्राइस इंडेक्स फोर इंडस्ट्रियल वर्कर, यह सरकारी आंकड़ें हैं, जो गुरुदास दासगुप्त जी कोट कर रहे थे, 10.5 प्रतिशत मई के महीने में बढ़ गया। ....**(व्यवधान)**....

DR. BIPLAB DASGUPTA: If everything is right, then in what way is it wrong?

श्री यशवंत सिन्हा: वह मंथली आंकड़े आते हैं, डब्ल्यू०पी०आई० वीकली आंकड़े आते है। जून के महीने मैं हम देखेंगे, फिर जुलाई के महीने में देखेंगे, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक चढ़ाव आज के दिन आया है।....**(व्यवधान)**...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is it correct to calculate inflation on WPI?

SHRI YASHWANT SINHA: I am saying that there are various methods of calculating inflation. It is calculated on the basis of the wholesale price index; it is calculated on the basis of the consumer price index for industrial workers; it is calculated on the basis of the consumer price index for agricultural workers. These are the statistics, these are the figures which the Government of the day publishes without holding back anything.

3.00 P.M.

आज के दिन आपने कहा कि 12 प्रतिशत हो गया होगा, 14 प्रतिशत हो गया होगा, मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास मई के आंकड़े हैं और अभी बाकी आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन इसी बीच मैंने कहा है अपने वक्तव्य में और यहां मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि जो खाने का तेल है, वह एक विशेष परिस्थिति में फंस गया। इस बार यह दुर्भाग्य रहा। आपने कहा कि किस्मत की बात है। हो सकता है कि किस्मत की बात हो क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में भी एक संकट आ गया। यह हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि जब हमारे देश में संकट आया तो उसी समय मलेशिया और इंडोनेशिया में भी संकट आ गया और खाने के तेल जिन्हें हर साल यहां के व्यापारी ओ०जी०एल० के अंतर्गत इंपोर्ट करते थे, इस बार उन्होंने कम इंपोर्ट किया क्योंकि वहां पर इसकी कीमतें 200 डॉलर प्रति टन अधिक हो गई थीं। मलेशिया और इंडोनेशिया के मार्केट में कीमतों में वृद्धि हुई थी। पिछले दिनों जब यहां चर्चा हो रही थी, उस समय भी किसी सदस्य का प्रश्न था। उसका उत्तर देते समय मैंने इस बात को रखा था कि हमारी मांग के चलते जो आपूर्ति होनी चाहिए, जो आयात होना चाहिए, वह आयात नहीं हुआ। जब आयात नहीं हुआ तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहे। जब हमने देखा कि कीमतें बढ़ रही हैं तो हमने तत्काल 2 कदम उठाए। एक कदम तो यह उठाया कि इंपोर्ट ड्यूटी में 10 प्रतिशत की छूट दे दी और दूसरा यह किया कि सरकार की तरफ से फैसला किया कि डेढ़ लाख टन हम खाने का तेल मंगाएंगे ईस्ट एशिया से और उसको हम पी०डी०एस० के माध्यम से बेचेंगे।

महोदया, इन्होंने कहा कि हम व्यापारियों की पार्टी हैं, इसलिए ट्रेडर्स की पार्टी हैं, इसलिए ट्रेडर्स के प्रति हम सॉफ्ट हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। आप देखिए कि एक जनवरी, 1998 से लेकर आज के दिन तक पूरे देश में 22,641 रेड्ज़ हुए हैं, 963 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 990 लोगों का प्रोसीक्यूशन हुआ है, 555 लोगों का कन्विक्शन हुआ है और इन रेड्ज़ में ज़ब्त की गई वस्तुओं की कीमत 561 लाख रुपए है।

This is the statistics which has been given.

†[ ]Transilteration in Arabic Script

अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में यह हुआ है कि 180 रेड्ज़ पड़ी हैं जनवरी से लेकर आज तक और आज सुबह मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि जितनी सख्ती करनी होगी उतनी सख्ती हम करेंगे लेकिन हम होर्डिंग को, जमाखोरी को नहीं बढ़ने देंगे और मैं आज के दिन यह कहना चाहता हूं कि ....**(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: But, there is no impact on the price rise.

श्री यशवंत सिन्हा: मैं बता रहा हूं आपको। हमारे सहयोगी श्री बरनाला जो खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने 16 जुलाई को सारे मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि—

> "It appears that some of the unscrupulous traders are indulging in hoarding of these commodities, to create artificial scarcity in the market. It is, therefore, imperative that effective and punitive action is taken under the existing provisions of the law against speculators, hoarders, blackmarkeeters and profiteers indulging in unfair trade practices."

सारे मुख्यमंत्री को यह पत्र सरकार की तरफ से भेजा गया है और जो फूड मिनिस्ट्री के सचिव हैं, उन्होंने 14 जुलाई को सारे राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास भंडार में बहुत अनाज है और आप कृपया उसको लिफ्ट कीजिए ताकि गेहूं, चावल और चीनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा न हो। जो पी०डी०एस० से जाता है, वह माल वहां तक पहुंचना चाहिए और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसको फौलो-अप करेंगे।

महोदया, यहां पर सुझाव दिया गया कि हम राज्यों से बात करें। अभी यह पत्र गया है अगर आवश्यकता हुई तो हम हरेक राज्य के आपूर्ति मंत्रियों की बैठक बुलाकर निश्चित रूप से इस विषय पर विचार करेंगे कि जो होर्डर्स हैं, जो जमाखोर हैं, इनके खिलाफ और तेजी से हम कैसे कार्यवाही कर सकते है।

महोदया, मैं आज के दिन सरकार की इस प्रतिबद्धता को बहुत मजबूती के साथ दोहराना चाहता हूं कि कीमतों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं ताकि हम इनके ऊपर नियंत्रण पा सकें। वक्तव्य में मैंने कहा है, इसके आंकड़े मेरे पास है और दिल्ली की सरकार ने जो पहल की है, उसके तहत लगभग 100 आऊटलैट्स से प्याज और आलू बिकना शुरू हो गया है। ताकि कीमतों के ऊपर कुछ नियंत्रण हम पा सकें। तो इस प्रकार जो सारी चीजें हैं...**(व्यवधान)** नहीं, अब नहीं है तो नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: उतने पर तो नहीं बिक रहा है।

†[श्री मोहम्मद सलीम: उतने पर तो नहीं बिक रहा है।]

श्री यशवंत सिन्हा: बिक रहा है, अब आप कहदें कि नहीं बिक रहा है, तो मैं कैसे स्वीकार करलूं।

उपसभापति: मंत्री जी, I think, we should look at the watch.

श्री यशवंत सिन्हा: सुपर बाजार अकेला आउटलेट नहीं है, सौ सफल और दुनियां भर के दूसरे कोआपरेटिव आउटलेट्स हैं जिसके माध्यम से इन चीजों की आपूर्ति दिल्ली में की जा रही है, दिल्ली की सरकार ने यह पहल की है। आज सदन में इस चर्चा के माध्यम से महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, उस निवेदन को दोहराना चाहता हूं, यहां पर कहा गया कि राज्य सरकारों की भी साझेदारी इसमें है—दो मायने में। एक मायने में, पी०डी०एस० को हमको मजबूत करके रखना है, अब यहां पर आंकड़े देने का समय मेरे पास नहीं है। पी०डी०एस० को मजबूती के साथ हम चलाएं और हमारे पास जैसा कि हमने कहा कि गल्ले की कमी नहीं है जितनी ...**(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Is there any Public Distribution System?

SHRI YASHWANT SINHA: Of course, it is there. It is as good as you left it, if not better. So, it is there and we are committed to supply to the people who are below the poverty line and above the poverty line. Everything is going according to their entitlement under the PDS. I have figures with me, कि कहां-कहां कितना जा रहा है। कहीं कई राज्यों में कमजोरी नजर आ रही है ऑफटेक में, उनको विशेष

†[ ]Transilteration in Arabic Script

तौर पर हमने कहा है कि आप अपना आॅफटेक इम्प्रूव करें, लेकिन...(व्यवधान)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Then, what has gone wrong? ...*(Interruptions)*... You are saying that everything is right. What has gone wrong then? There must be some explanation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Biplab Babu, please sit down. I am not allowing you to say anything...*(Interruptions)*... Mr. Biplab Dasgupta, please sit down...*(Interruptions)*... would not allow...*(Interruptions)*... You take my permission and speak...*(Interruptions)*... Let him answer. He has not finished yet...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, he is evading all questions.

SHRI YASHWANT SINHA: I am not evading even a single question. I have attempted, to the best of my ability, to answer all specific questions that you have raised. Now, if you are determined to make a political point and walk out, I cannot prevent it...*(Interruptions)*... Madam, I appealed with both hands even at the time of debate on the Finance Bill, "Please do not walk out. Please, listen to what I have to say." There is no point in getting angry over all these things. This is a national problem. Madam Deputy Chairperson, you have said yourself that this is a problem which is confronting the people of this country and I am taking the blame only because today, I happen to be present in the Government. Otherwise, somebody else would have taken the responsibility. This is what the whole situation is about. I have said confidently, that we hope when pre-Kharif arrivals come to the market, the pressure on prices will abate and these seasonal factors will start declining and also the price rise will come down. I mentioned in my statement that out of 8% of the WPI, 2% is accounted only for these seasonal factors. This means, it is not only onions and potatoes, which is a very important point raised by Shri Ramdas Agarwalji, but also edible oil, pulses and also medicines. For instance, there has been an increase of 11% over the last year...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is 25%.

SHRI YASHWANT SINHA: 11% is my figure. Your figure may be different.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How can there be any increase in the prices of medicines when there is no seasonal problem? ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: I never said that it is only because of seasonal problem. I never said that medicines are like potatoes ...*(Interruptions)*...

SHRI MD. SALIM: The earlier Government must have done something on that ...*(Interruptions)*...

उपसभापति: मंत्री जी। आप उधर देखकर बोलते हैं इसलिए रिएक्शन होता है।

I would not react at all to whatever you say.

श्री यशवंत सिन्हा: हां, यह बात सही है। मैं यह कहना चाहता हूं मैडम् डिप्टी चेयर पर्सन, कि सारी सरकारों के सामने चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे यूनाईटड फ्रंट की सरकार रही हो उनको भी इस तरह की परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ा है जब मौसमी कारणों के चलते कुछ कीमतें भागी हैं तथा और कारणों के चलते भी कुछ कीमतें भागी हैं। हर सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह कीमतों के ऊपर नियंत्रण पाए। इस सरकार का भी दृढ़ निश्चय है कि हम कीमतों के ऊपर काबू पाएं और इसके लिए जो आवश्यक क़दम हमने उठाए हैं उसके अलावा जितने और कदम उठाने की आवश्यकता होगी, समय-समय पर हम उन क़दमों को उठाएंगे। लेकिन बढ़ती हुई कीमतों का सर कुचल कर हम रख देंगे, यह मैं आज के दिन सदन से वायदा करना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Message from the Lok Sabha, Mr. Secretary General ...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, I wanted to raise a point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to raise? ...*(Interruptions)*...I cannot understand if so many people speak together

...(*Interruptions*)...I cannot understand if everybody starts speaking ...(*Interruptions*)...I am not following anything ...(*Interruptions*)... Please sit down ...(*Interruptions*)...We have a messagae from the Lok Sabha ...(*Interruptions*)...No. Now, message from the Lok Sabha .

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok SAbha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 1998.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

Madam, I lay the Bill oh the Table

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Steel rise in the inflation and its adverse impact on the Economy and the People—Contd.

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, यह महंगाई का सवाल है। ...(**व्यवधान**)...आज का यह विषय है।...(**व्यवधान**)...उसको मंत्री जी ने खुद माना है। ...मंत्री जी ने खुद माना है कि महंगाई हो रही।...(**व्यवधान**)...

†[شری محمد سلیم: میڈم یہ مہنگائی کا سوال ہے ...''مداخلت'' ...آج کا یہ وشے ہے ...''مداخلت'' ...اسکو

†[ ]Transilteration in Arabic Script

منتری جی نے خود مانا ہے ...''مداخلت'' منتری جی نے خود مانا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے ...''مداخلت'' ...]

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to ask? (*Interruptions*) So many people speak together. I cannot understand. (*Interruptions*) I cannot understand if everybody speak together. (*Interruptions*) I am not following anything. (*Interruptions*) Please sit down. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, the hon. Minister's statement is completely unsatisfactory. (*Interruptions*) Madam, the statement of the hon. Minister is completely unsatisfactory. There is no political...(*Interruptions*) He has completely failed to satisfy that he has a *bona fide* desire to control the inflation, which is ruling the country. (*Interruptions*) Therefore, we are walking out in protest.

[At this stage some hon. Members left the Chamber]

श्री संघ प्रिय गौतम: मैडम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये लोग केवल आलोचना कर रहे हैं। ये सुझाव दें कि महंगाई कैसे रुक सकती है? इनके पास क्या सुझाव हैं। ये बताएं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, I want to raise a point. The hon. Minister was trying to do a *post mortem* and compare. I want to draw the attention of the hon. Minister to the post-Pokhran stage. While presenting the Budget, he promised this country a new India. He promised milk and honey. So, there was no question of comparing with what happened in the past. He never promised that. Therefore, I wanted to intervene at that time. Madam, we are also walking out in protest.

[At this stage some hon. Members left the Chamber]